प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां

)नवंबर, 2019)

*****

मुख्य कार्यकलाप और उपलब्धियाँ

- अभी तक 60,000 आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) को मंजूरी दी जा चुकी है। एचडब्ल्यूसी पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 24,709 एच एंड डब्ल्यूसी को 3 दिसंबर, 2019 तक संचालित कर दिया गया है।
- कायाकल्प के तहत, 20439 सुविधा केंद्रों, 4614 सुविधा केंद्रों और 2185 सुविधा केंद्रों का क्रमश: आंतरिक मूल्यांकन, पीयर मूल्यांकन और वाह्य मूल्यांकन किया गया। अब तक 2019-20 के लिए यह आंकड़ा 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है।
- भारत में जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों में उत्तम और अनुकरणीय पद्धतियों और नवाचार पर 6ठा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 16-18 नवंबर, 2019 के दौरान गांधी नगर, गुजरात में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वास्थ्य की विभिन्न चुनौतियों को दूर करने और एनएचएम के तहत जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रबंधन में अपनाई गई उत्तम पद्धतियों और नवाचारों को आपस में साझा करना और इनसे सीख लेना था।
- मीज़ल्स रूबेला (एमआर) अभियान 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा हो गया है। 14 नवंबर, 2019 तक 32 करोड़ से अधिक बच्चों का इस अभियान के तहत टीकाकरण किया गया।
- बचपन में नयूमोनिया के प्रबंधन पर संशोधित दिशानिर्देश और सांस (न्यूमोनिया को सफलतापूर्वक निरस्तर करने के लिए सामाजिक जागरुकता और कार्रवाई) अभियान पर दिशानिर्देश को नवंबर, 2019 में गांधी नगर, गुजरात में राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी नवाचारों पर सर्वोत्तम पद्धतियां/नवाचार-6ठे राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के आयोजन के दौरान जारी किया गया।
- मंत्रालय ने अपने रीप्रोड्यूस एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आईसीडीएससीएएस के साथ समेकित करने के लिए सामान्य लाभार्थी पंजीकरण प्रणाली को विकसित करने का काम शुरू किया है ताकि पीएचआई (व्यक्तिगत स्वास्थ्य पहचानकर्ता) का प्रयोग करते हुए अनुप्रयोग को अंतरप्रचालनीय बनाया जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजीट हेल्थ ब्लूप्रिंट की सिफारिशों के अनुसार लाभार्थियों को एक प्राथमिक कुंजी के रूप में पीएचआई आवंटित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दोनों पीएचआई को क्रियान्वित करने में लगे हुए हैं जो लाभार्थी को दो अनुप्रयोगों आरसीएच पोर्टल और आईसीडीएससीएस एप्लीकेशन में जोड़ेगा। नतीजों की पुष्टि के लिए छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के महुदा गांव, ब्लॉक पाटन में प्रूव ऑफ कॉन्सेप्ट की प्रक्रिया चल रही है।
- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स-भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा एमबीबीएस के लिए संशोधित पाठ्यक्रम अधिसूचित किया गया है।
- नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के चरण-III के तहत 23 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने हेतु केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत 9 मेडिकल कॉलेजों में 450 स्नातक सीटें बढ़ाई गई हैं।
- 01 स्नातकोत्तर कोर्स को मान्यता देने संबंधी अधिसूचना और 17 मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस कोर्स के संबंध में संबद्धता (एफिलिएशन) को बदलने के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
- राष्ट्रीय डिजीटल हेल्थ ब्लूप्रिंट (एनडीएचबी) की रिपोर्ट को व्यय विभाग के समक्ष 'सिद्धांत:' अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

- अंतर्विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करने और 'इन्जेक्शन के जरिए नशीली दवाओं के सेवनकर्ताओं के लिए समेकित सेवा पैकेज' तैयार करने की दिशा में हुई प्रगति पर 18 नवंबर, 2019 को आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आईडीयू के लिए समेकित सेवा पैकेज प्रदान करने की पद्धतियों को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय वायरल हेपटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नशा मुक्ति कार्यक्रम, क्षय रोग नियंत्रण हेतु संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम और राष्ट्रीय नशा निर्भरता उपचार केंद्र-एम्स के प्रतिनिधियों से एक तकनीकी समिति गठित की जाए। यह भी निर्णय लिया गया था कि नशा और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का साझा कार्यक्रम (यूएनएआईडीएस) आदि जैसी संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न विशेष एजेंसियों से जानकारियां ली जाएं।
- सीजीएचएस अस्पताल/औषधालयों/आरोग्य केंद्रों तथा सीजीएचएस के पैनलबद्ध अस्पतालों/प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से आरएनटीसीपी सेवाएं प्रारंभ करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस क्रियाकलाप के लिए दिल्ली के दो जोनों में 25 से 28 नवंबर, 2019 के दौरान सीजीएचएस के चिकित्सा अधिकारियों के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ), संयुक्त राज्य अमरीका और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार के बीच 18 नवंबर, 2019 को सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए।
- बकरी/भेड के दूध, मिल्क पाऊडर में सोडियम की कुल मात्रा और कुछ नए दुग्ध उत्पादों नामत: मध्यम वसा छेना/पीन, लवण-जल में वे चीज और चीज के मानकों के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य पदार्थ) पांचवा संशोधन विनियम, 2019 को अधिसूचित किया गया।
- 'खाद्य, ग्रह, स्वास्थ्य हेतु केंद्र' स्थापित करने के लिए एफएसएसएआई और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) मसूरी, उत्तराखंड के जन प्रणाली केंद्र (सीपीएसएम) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसका उद्देश्य है अधिकारियों को जन मानस और ग्रह दोनों के लिए स्वस्थ भोजन संबंधी नीतियों और कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक तरीके से सोचने और कार्य करने की क्षमता विकसित करना।
- नवंबर, 2019 माह में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हुई प्रगति निम्नानुसार है:

मीट्रिक	01.11.2019 की स्थिति के अनुसार	01.12.2019 की स्थिति के अनुसार	नवंबर, 2019 के दौरान प्रगति
जारी ई-कार्ड	643,04,197	678,13,497	35,09,300
अस्पताल में भर्ती	56,83,823	64,50,119	7,66,296
अस्पताल में भर्ती हेतु अधिकृत राशि)में करोड़(	8,312.30	9,408.90	1,096.60
पैनलबद्ध अस्पताल	18,750	19,749	999
कुल कॉल्स जिनका उत्तर एनएचए कॉल सेंटर (14555) द्वारा दिया गया।	45,92,897	46,33,603	40,706
mera.pmjay.gov.in पर कुल प्रयोक्ता	158,64,837	163,80,524	5,15,687
पीएमजेएवाई एप्लीकेशन के इंस्टालेशन की कुल संख्या	8.96	9.09	0.13
नोट: उपर्युक्त सूचना राज्य स्कीमों के साथ-साथ पीएमजेएवाई के तहत लाभान्वित हुए लाभार्थियों के संबंध में है। राज्यों द्वारा अपनी सूचना प्रौद्योगिक प्रणालियों का प्रयोग करके पीएमजेएवाई लाभार्थियों हेतु अतिरिक्त 4.68 करोड़ राज्य कार्ड बनाए गए।			

****